MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 12th November, 1973."

The motion was adopted.

---

13. 02 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

ALLEGED FAILURE OF GOVERNMENT TO INFORM THE HOUSE ABOUT ABOLITION OR REDUCTION OF EXPORT DUTY ON JUTE GOODS

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो सवाल उठा रहा हूं वह कम से कम 100 करोड़ रुपये का मामला है।

18 जुलाई, 1973 को सरकार ने आसाम बाटम किस्म के पाट के लिए 157.68 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कलकत्ता डिलीवरी का दाम निर्धारित किया गया। 19 अगस्त को व्यापार मंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता में एक प्रेस सम्मेलन किया। उसमें उन्होंने कहा कि पाट के सामान पर निर्यात शुल्क घटाने या समाप्त करने का सुझाव उनके मंत्रालय ने दिया है ताकि कृत्रिम सामानों की तुलना में पाट के सामानों की स्पर्द्धा करने की क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बढ़ सके। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनके सुझाव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल मालूम पड़ रही है।

व्यापार मंत्री ने, मेरी राय में, दो किस्म औचित्य भंग किया। पहला, वित्त मंत्रालय से अन्तिम सूचना प्राप्त होने के पहले ही उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में निर्यात शुल्क घटाने और समाप्त करने की घोषणा की और यह भी कह दिया कि वित्त मंत्रालय इसके पक्ष में है। दूसरा औचित्य भंग यह हुआ कि व्यापार मंत्री ने ऐसे सुझाव की घोषणा कलकत्ते में एक प्रेस सम्मेलन में की जिसमें सरकारी खजाने को 18 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला था अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कई बार फरमाया है कर सम्बन्धी मामला लोक सभा के सामने सबसे पहले आना चाहिए न कि प्रेस सम्मेलनों के सामने, खास कर के जब कि लोक सभा का सत्र चल रहा हो।

26 सितम्बर, 1973 को केन्द्र सरकार ने जूट मिल मालिकों के ऊपर आदेश जारी किया कि अक्तूबर के अन्त तक कच्चे पाट की 14 लाख गाठें वह निर्धारित दाम पर खरीदें। व्यापार मंत्री ने जूट कारपोरेशन को भी यह आदेश दिया था कि वह भी उत्पादकों से निश्चित दाम पर 15 लाख गांठें खरीद लें।

लेकिन जूट मिल-मालिकों ने, न ही जूट कारपोरेशन ने सरकारी आदेशों का पालन किया। सरकार ने निर्धारित दामों में जो क्विंटल पीछे 12 रुपये की छूट दे दी थी उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ। स्वयं श्री चट्टोपाध्याय कलकत्ता में यह कहने के लिए बाध्य हो गये कि उनको जूट उद्योग के व्यवहार से घोर निराशा हुई

है। उन्होंने स्वीकारा कि सरकार ने निर्यात शुल्क घटाने तथा समाप्त करने का जो असाधारण कदम उठाया था वह असफल हो गया है क्योंकि न जूट उद्योग ने जूट की खरीद तेजी से करने का काम किया न उसने अपने सामानों के दामों को कम कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा करने की क्षमता को बढ़ाया।

जैसा कि कलकत्ता के "कैपिटल" साप्ताहिक ने कहा, निर्यात शुल्क घटाने के बाद जूट के सामानों के दामों में जो परिवर्तन हुआ है वह अपेक्षा के बिल्कुल बरखिलाफ था। हेसियन और सैकिंग के दामों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और निर्यात शुल्क का जो असर होना चाहिए था बिल्कुल उसके उल्टा काम हो गया है। खरीदने वालों को दाम निर्यात शुल्क घटाने के बाद अधिक ही देने पड़ रहे हैं। यह सर्वविदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय दाम अन्दरूनी दामों पर ही निर्भर करते हैं।

जूट सामानों के दामों में 20 प्रतिशत से अधिक इजाफ़ा होने के बाद भी व्यापार मंत्री वित्त मंत्रालय के साथ सांठ-गांठ करके जूट उद्योग को और अधिक रियायतें देने पर आमादा हो गये। पाट खरीदने के लिए जूट उद्योग को रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की सम्मति से 30 करोड़ रुपये का कर्जा दिया जा रहा है।

व्यापार मंत्री की अयोग्यता और गलत नीतियों के कारण 20 करोड़ रुपया सीधा जूट उत्पादकों से छीन कर जूट उद्योग को दिया गया है। इसके ऊपर निर्यात शुल्क घटा कर और समाप्त कर उसको 18 करोड़ रुपये की दक्षिणा भी दी गई है। इसमें कलकत्ते के बाहर सस्ते दाम से जो जूट खरीदा गया उससे उद्योग को जो लाभ हुआ उसको तो जोड़ा ही नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आजादी के बाद इतना मुनाफा जूट उद्योग को पहले कभी नहीं हुआ था। दर्शन के प्राध्यापक महोदय ने जूट उद्योग के हित-सम्बन्धी लोगों के दलाल (ब्रोकर) का काम किया है और खरीदार तथा उत्पादकों को लूटा है।

इसलिए मेरी मांग है कि :—

1. निर्यात शुल्क को फिर से लाद दिया जाये क्योंकि वैकल्पिक कृत्रिम माल की "कैपिटल" साप्ताहिक के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में कमी है;

2. बी० ट्विल सरकार अपनी आवश्यकताओं के लिए 100 बैग के रेट 240 रुपये की दर से खरीदे। अन्य सामान भी वह नियंत्रित दाम से जूट उद्योग से ले ले;

3. सरकार जूट उद्योग के ऊपर एक नई लैवी या सेस लगा दे और उससे जो राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल वह जूट की खेती के सुधार के लिए जूट उत्पादकों को मदद के रूप में दे दे।

मंत्री महोदय ने अपनी अयोग्यता का जो इजहार किया है, जूट हित सम्बन्धियों के

[श्री मधु लिमये]

सामने जो घुटने टेके हैं, और लोक सभा को विश्वास में लेने से जो इन्कार किया है, उसके लिए वे सदन से माफी मांगें।

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): The Ministry of Commerce have for some time now been concerned with the downward trend in the export of jute goods and on the basis of available information it came to the conclusion that the main reason for this trend in the exports was due to competition from the synthetic substitutes. The price of synthetics subs- ruling uniformly at a lower level and with the fact that there was a large capacity already created, it was expected that the price would further go down with the increase in the scale of production. We have been steadily losing the United States market, and, but for the gains that we have been able to make in East European Countries, we would have been much worse off. Also the price of jute goods produced by Bangladesh were on an average lower by about 5 to 10 per cent as compared to the price of Indian products. While efforts to bring about cost reduction was considered essential, since this was by its very nature a long-term effort, it was felt that the abolition or reduction of export duties would have the effect of restoring the competitive position of Indian jute products. This assessment was made on the basis of empirical data available during the second quarter of 1973 and on the basis of reports from various markets. The matter was therefore, taken up with the Ministry of Finance and a case was made out for the reduction of export duty on sacking and hessian. Earlier, the Ministry of Finance had agreed to reduction on export duty on carpet backing and this had already had a healthy impact on export of carpet backing. The industry had been continuously pressing for complete abolition of export duty and it is in this context that in a meeting on "the problems and prospects of the jute industry" in Calcutta held on the 18th August, 1973 that I gave an indication that the question of affording fiscal relief on hessian and sacking was under the active consideration of the Government and I also mentioned that some positive action would be taken. There was no announcement—I repeat, there was no announcement —of reduction, abolition etc., of export duty on jute manufactures in the meeting. Since the final decision in regard to adjustment of export duty rests with the Ministry of Finance, it is they who could make any official announcement in this regard. The actual announcement in regard to reduction of export duty was by a notification by the Ministry of Finance on the 28th August, 1973. It is, therefore, submitted that the statement quoted in the press does not amount to an announcement of reduction or abolition of export duty and was merely an indication of the fact that the Government had taken due note of the representations of the industry and was having the matter examined in its proper perspective. I say, the Ministry has thought. Thought does not mean action. And the Ministry can express its thought on a very vital matter when it was being taken up. The question was also put to me.

I would, therefore, submit that no breach of privilege is involved.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना मामूली नहीं है। इन्होंने कई गलत बयान तो किये ही हैं। लेकिन मैं आप से चाहता हूं कि आप इस के ऊपर निर्णय दीजिए। आप सुन तो लीजिए हमारी बात।

MR. SPEAKER: I am sorry I cannot give any ruling on it. Under 377 you were asked to invite the attention of the Minister. And the Minister has made his own case. Beyond that, I have nothing else to do.

SHRI MADHU LIMAYE: Are you satisfied with that.

MR. SPEAKER: It is the decision of the House. There is no question of my being satisfied with this or not satisfied with this at all.

श्री मधु लिमये : बिल्कुल है ।

MR. SPEAKER: There is no question of my giving a ruling on it. Please do not take away discussion under Rule 377 beyond its limit.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, क्या आप की यह रूलिंग है कि टैक्सेशन के मामले में इस तरह बाहर बोला जाए ? आप कई बार रूलिंग दे चुके हैं । आप बदलना चाहते हैं अपनी रूलिंग को तो दूसरी बात है । 100 करोड़ रु० बर्बाद हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है ।

MR. SPEAKER: We now adjourn for lunch to re-assemble at fifteen minutes past two.

13.14 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at ninteen minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Re. RETRENCHMENT IN FOOD CORPORATION OF INDIA (U.P. REGION)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chattopadhyaya.

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur): May I make one submission I had given notice of it earlier this morning. The services of more than 800 employees of the Food Corporation of India (UP Region) have been terminated and more than 288 people have been superannuated, that is, compulsorily retired. When the Food Corporation has decided to tackle the food situation in the country, how is it that in the UP region, about a thousand men are going to be retrenched? Prof. Sher Singh is here, and I would request you, Sir, to ask him to make a statement. This is a serious affair because they are going on strike shortly.

Re. CANCELLATION OF 250 PASSENGER TRAINS DUE TO SCARCITY OF COAL

श्री मधु लिमये (बांका): दो बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले के अभाव के नाम पर ढाई सौ गाड़ियां बन्द हो चुकीं हैं । आज की खबर है कि अकेले वाराणसी डिविजन में नार्थ ईस्टर्न रेलवे की कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं । जिस इलाके से आप आते हैं वहां की नार्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे पर भी गाड़ियां रद्द हो गई हैं । नादर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ-ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे सब में बन्द हुई हैं । स्टील और मांइज के मिनिस्टर कहते हैं कि कोयले की पैदावार इस साल ज्यादा है विगत साल की तुलना में । यह क्या मामला है ? इसके ऊपर रेलवे मंत्रालय को सफाई करनी चाहिये और इनको भी खुलासा करना चाहिये । एविएशन फ्यूल के अभाव में 24 फ्लाइंग क्लबज बन्द हो रही हैं जहां नौजवानों को ट्रैनिंग मिलती है । ये क्लबें सब बन्द हो